CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner

डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार और एनडीडीबी एक डेयरी कंपनी बनाएंगे

दुग्ध किसानों के आर्थिक विकास में तेजी लाने और डेयरी क्षेत्र को अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के प्रयास में, मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एनडीडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार और एनडीडीबी के संयुक्त समन्वय से एक संयुक्त कंपनी का गठन किया जाएगा जो डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तय करेगी और उस पर कार्य करेगी।

कंपनी के अध्यक्ष पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री होंगे क्योंकि कंपनी का गठन राज्य सरकार और एनडीडीबी के बीच समान शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग को अक्टूबर तक कंपनी की ओर से सभी तौर-तरीकों को पूरा करने को कहा ताकि कंपनी नवंबर तक अपना काम शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध क्रांति को नई गति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

डेयरी शब्द का उपयोग करने वाले प्लांट आधारित दूध उत्पादों के विक्रेताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्लांट आधारित दूध उत्पाद बेचने वाली पांच कंपनियों को एफएसएसएआई के आदेश के तहत किसी भी कठोर कदम से संरक्षण दिया, जिसमें उनके उत्पादों के लिए "डेयरी शब्द" का उपयोग करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, जिसमें ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों द्वारा डी-लिस्टिंग भी शामिल है। आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने स्पष्ट किया कि संबंधित कंपनियों को उचित नोटिस के बाद अधिकारी कानून के अनुसार जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

जज ने हर्शे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राक्यान बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, आई-स्टोर डायरेक्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्रम्स फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और वेगनारके एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और एफएसएसएआई से जवाब मांगा। अदालत ने आदेश दिया, "अगली तारीख तक, आक्षेपित आदेश जहां तक वे सीधे दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश देते हैं, रुके रहेंगे।"

डेयरी किसानों ने अमूल डेयरी से बकाया भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

प्रकाशम जिले, आंध्र प्रदेश में डेयरी किसानों, जिन्हें अमूल डेयरी को दूध उपलब्ध कराने के लिए भुगतान नहीं मिला, ने सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि उनका बकाया तुरंत भुगतान किया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और सोमवार को संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. आंध्र प्रदेश के महासचिव रायथु संघम केवीवी प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण, किसानों ने दूध वितरण बंद कर दिया और जिले में अमूल के दूध संग्रह केंद्र 246 से घटकर 130 हो गए। उन्होंने मांग की कि सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए और किसानों को तुरंत भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

एपी रायथू संघम के जिला सचिव हनुमारेड्डी ने कहा कि महीनों से काम का भुगतान नहीं होने से दूध संग्रहण एजेंटों को डेयरी किसानों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमूल डेयरी और एपीडीडीसी के बीच समन्वय की विफलता के कारण डेयरी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से किसानों के साथ-साथ एजेंटों को भी बकाया भुगतान करने की मांग की।

पश्चिम बंगाल सरकार 400 बांग्ला डेयरी आउटलेट स्थापित करेगी

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए बांग्ला डेयरी के 400 आउटलेट स्थापित करने जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक आउटलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मदर डेयरी को "बांग्ला डेयरी" के रूप में फिर से नामित करने का निर्णय लेने के बाद यह कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक संवर्धन बोर्ड की बैठक के बाद, मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने राज्य सरकार के आउटलेट स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। साथ ही राज्य सरकार हरिंघाटा में मौजूदा एक की तर्ज पर चार पोल्ट्री और डेयरी फार्म स्थापित करेगी।

राज्य में लगभग 390 करोड़ अंडों की कमी है जबकि वार्षिक आवश्यकता 1450 करोड़ की है, जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश से इसका आयात किया जा रहा है। राज्य सरकार लेयर फार्म स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है क्योंकि इससे बंगाल को चूजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। बायो कंपोज्ड फार्म भी स्थापित किए जाएंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 342 करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आगे के विकास के लिए इस क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करेगा।

किसानों का डेटाबेस बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने सिस्को, जियो, आईटीसी, एनईएमएल और निन्जाकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक समूह सिस्को, कोलकाता स्थित कॉर्पोरेट प्रमुख आईटीसी, कमोडिटीज प्रमुख आईटी शाखा एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल), रिलायंस इंडस्ट्रीज की आईटी शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स और भारत की सबसे बड़ी ताजा उपज आपूर्ति श्रृंखला फर्म निन्जाकार्ट ने कृषि मंत्रालय के साथ देश में किसानों का डेटाबेस बनाने में केंद्र की मदद करने के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। पांचों फर्म कृषि क्षेत्र के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स (पीओसी) विकसित करेंगी।

पीओसी केंद्र को उन समाधानों को समझने में मदद करेगा जो उपलब्ध डेटा का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं और उनमें से कुछ, अगर किसानों के लिए फायदेमंद पाए जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। फर्मों ने पीओसी विकसित करने के लिए एक वर्ष के लिए नि:शुल्क आधार पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पायलट परियोजनाओं के आधार पर, किसान इस बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि कौन सी फसल उगानी है, किस किस्म के बीज का उपयोग करना है और अधिकतम उपज के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है।

कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, ईएसआरआई इंडिया टेक्नोलॉजीज, स्टार एग्रीबाजार और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी एमओयू साइन किए थे। कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 2021-21 के दौरान डिजिटल कृषि मिशन के निर्माण के हिस्से के रूप में एग्रीस्टैक बनाने के प्रयासों में तेजी लाने के साथ और अधिक कंपनियां पीओसी विकसित करने के लिए बोर्ड में आ सकती हैं।

स्टार्ट-अप: जेनफ्लो एआई - पशु चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक क्रन्तिकारी पहल

स्टार्ट-अप जेनफ्लो एआई एक उभरती हुई कंपनी है जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और योग्य विशेषज्ञों का उपयोग करके पशुधन स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद करना है। श्री नीतीश गौरव, एक कृषि पेशेवर, जेनफ्लो एआई के संस्थापक और सीईओ हैं, जिन्होंने योग्य पशु चिकित्सक द्वारा प्रत्येक पशुपालक किसान को सस्ती पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के सपने के साथ कंपनी की स्थापना की।

डेयरी किसानों को पशु रोगों से होने वाले भारी नुकसान से बचाने के लिए जेनफ्लो एआई उच्च शुल्क वाले अयोग्य पशु चिकित्सक द्वारा परामर्श पर निर्भरता को खत्म करने के मिशन पर है। जेनफ्लो एआई मोबाइल एप्लिकेशन एएचबी सुरक्षा के माध्यम से डिजिटल और भौतिक रूप से दोनों को जोड़कर पशुधन किसानों और योग्य पशु चिकित्सक दोनों की मदद करता है। ऐप को डिजिटल इमेज विश्लेषण और वीडियो कॉलिंग सुविधा के माध्यम से टेली-परामर्श और टेलीमेडिसिन नुस्खे जैसी उच्च अंत सुविधाओं के साथ शामिल किया गया है और साथ ही किसान दवा और पशुधन फ़ीड वितरण भी बुक कर सकते हैं या इसे निकटतम एएचबी सुरक्षा केंद्र में उपलब्ध करा सकते हैं।

एएचबी सुरक्षा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है जो एक क्लिक के माध्यम से कभी भी, कहीं भी मवेशियों के स्वास्थ्य की स्थिति को ट्रैक करता है। किसान को बस अपने जानवर के संक्रमित क्षेत्र की छवि पर क्लिक करने और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ हिंदी भाषा में कुछ प्रश्नों का पालन करने और ऐप के माध्यम से रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता है।

जेनफ्लो एआई मवेशियों में बांझपन की समस्या को हल करने के लिए खेत में अच्छी वीर्य गुणवत्ता के साथ डिजिटल एंडोस्कोपी सेवा (हाई-डेफिनिशन कैमरा आधारित वेजिनोस्कोपी) और कृत्रिम गर्भाधान भी प्रदान करता है, जो डेयरी उद्योग में सबसे उभरती समस्या में से एक है।

AHB SURAKSHA®
पशु आपका जिम्मेदारी हमारी

लैक्टालिस समूह की अनिक डेयरी ने सुभाषिस बसु को नया सीईओ नामित किया

डेयरी प्रमुख लैक्टालिस समूह के स्वामित्व वाली अनिक डेयरी ने सुभाषिस बसु को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। सुभाषिस बसु स्नैक्स निर्माता प्रताप स्नैक्स से आएंगे, जहां वह चार साल से अधिक समय से सीईओ हैं। प्रताप स्नैक्स में अपनी भूमिका से पहले, बसु पहले मदर डेयरी के साथ थे। प्रताप में, सुभाषिस बसु ने कंपनी को अपनी सार्वजनिक सूची में शामिल किया, और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्योर एन श्योर फ़ूड बाइट्स के माध्यम से मीठे स्नैक्स में विविधीकरण किया, जिसे बाद में मूल कंपनी के साथ एकीकृत किया गया।

GROUPE LACTALIS
ANIK

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, डेयरी और पेय पदार्थों की घरेलू खपत के बढ़ते रुझानों के बीच डेयरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दोहरे अंकों की वृद्धि देखी जा रही है। फ्रांस के लैक्टालिस समूह का हिस्सा लैक्टालिस इंडिया ने 2014 में तिरुमाला दूध डेयरी का अधिग्रहण किया, जिसके बाद उसने क्रमशः 2016 और 2018 में अनिक और प्रभात का भी अधिग्रहण किया।